दिनांकः 16.04.2016

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, वित्त
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय
जयपुर

2. आयुक्त
वाणिज्यिक कर विभाग
कर भवन, जयपुर ।

विषय :– उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी की अस्थायी वरिष्ठता सूची पर आपत्ति।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा हाल ही में उपरोक्त पदों की अस्थायी वरिष्ठता सूचियॉं जारी करके प्रभावित पक्षकारों से आपत्तियॉं चाही गई है। इस कम में निम्न आपत्तियॉं प्रस्तुत की जा रही हैः–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम.नागराज के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक राज्य/सरकार द्वारा निम्न तीन अनिवार्य शर्तों की पूर्ति प्रत्येक प्रकरण में संख्यात्मक आंकड़ों से नहीं की जाती है तब तक राज्य/सरकार को पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान करने का कोई अधिकार नहीं हैः–
   अ. एससी/एसटी वर्ग के नौकरी पा चुके लोगों का पिछडापन संख्यात्मक आंकड़ों से साबित करना ।
   ब. एससी/एसटी वर्ग का सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संख्यात्मक आंकड़ों से साबित करना।
   स. एससी/एसटी वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से सकल प्रशासनिक दक्षता की सुरक्षा पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा को संख्यात्मक आंकड़ों से साबित करना

   आप यह भली भांति जानते है कि केन्द्र सरकार ने संसद में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 16(4)(ए) में संशोधन के लिए जो 117वां संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके उद्देश्य वाक्य में यह स्पष्टतः स्वीकार किया है कि एससी/एसटी वर्ग के नौकरी पा चुके लोगों का संख्यात्मक आंकड़ों से पिछड़ापन साबित किया जाना संभव नहीं है। इस संशोधन प्रस्ताव एवं उद्देश्य वाक्य की फोटो प्रति संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य बताई गई तीन शर्तों में से पहली शर्त की पूर्ति ही असम्भव है। अतः उपरोक्त अस्थायी वरिष्ठता सूचियों को पदोन्नति में बिना किसी आरक्षण के प्रावधान के बनाया जावे और मेरे से कनिष्ठ एससी/एसटी वर्ग के जो भी अधिकारी/कर्मचारी मुझसे वरिष्ठ दिखाये गये है उनसे उपर मेरी वरिष्ठता निर्धारित की जावे।

2. राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त अस्थायी वरिष्ठता सूचियॉं जारी करने से पहले कोई आंकड़े नहीं जुटाये गये है, कोई कवायद नहीं की गई है, कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, जिससे कि संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तीन शर्तों की पालना साबित की जा सके। अतः राज्य /सरकार को पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने का कोई अधिकार नहीं है।

(लगातार—2)

18.04.16

3. इस कम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा दायर की गई याचिका संख्या 14176/2012 लम्बित है इसमें विभाग/सरकार द्वारा अभी तक कोई न्यायोचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में संवैधानिक प्रावधानों एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना करते हुये पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करके वरिष्ठता सूचियॉं जारी करना न्यायपालिका की अवमानना है।

4. कृपया केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आवश्यक मानदण्डों का अवलोकन करे जो पत्र कमांक कमशः 17020/18/2012–एस.सी.डी. (आर.एल.सैल) दिनांक 18.06.2013 एवं 16016/6/2011-C&LM-I (Rajasthan) दिनांक 13.06.2013 की फोटो प्रति के रूप में आवेदन के साथ संलग्न है। इन अनिवार्य मानदण्डों का अवलोकन करने से प्रकटतः प्रमाणित होता है कि एससी/एसटी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में आ जाता है वह इन मानदण्डों में से एक की भी पूर्ति करने में सक्षम नहीं रहता है। अर्थात अनुच्छेद 16(4)(ए) के परिपेक्ष में उसे एससी/एसटी में शामिल नहीं माना जा सकता। अतः उसे पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देय नहीं है।

5. आपकी जानकारी के लिए केन्द्र सरकार का पत्र कमांक 11030/01/2013-C&LM-I दिनांक 26.08.2013 ,माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 18.02.2014 को दिये गये निर्णय की प्रति एवं राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2014 को जारी आदेश की प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है, जिससे प्रकटतः प्रमाणित है कि राजस्थान में "मीणा" (MEENA) समुदाय के लोग सामान्य वर्ग में है। मेरी यह जानकारी में आया है कि मुझसे कनिष्ठ मीणा समुदाय के अनेक कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का अविधिक लाभ देते हुये मुझसे वरिष्ठ बताया गया है। अतः आप मुझसे कनिष्ठ मीणा (MEENA) समुदाय के ऐसे सभी अधिकारियों को पुनः मुझसे कनिष्ठ दर्शाते हुये संशोधित वरिष्ठता सूचियॉं जारी करने का कष्ट करे।

उपरोक्तानुसार मेरी आपत्तियों का यथाशीघ्र निस्तारण करके मुझे सूचित करने का कष्ट करे अन्यथा मुझे मजबूर होकर न्यायालय की शरण में जाना होगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

सादर,

भवदीय,

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(पाराशर नारायण शर्मा)
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सर्किल–एच, संभागीय कर भवन,
झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

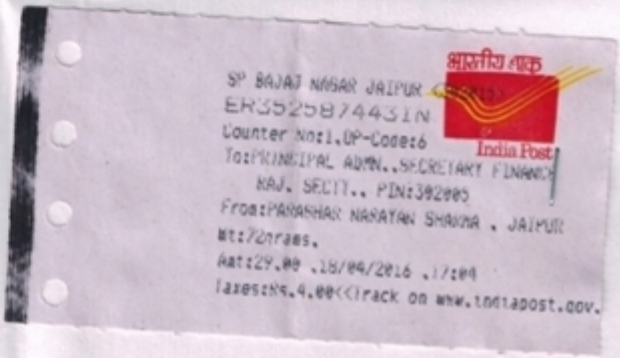

Bill No. XLVIII of 2012

THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED SEVENTEENTH AMENDMENT) BILL, 2012

A

BILL

further to amend the Constitution of India.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Constitution (One Hundred Seventeenth Amendment) Act, 2012.

(*2*) It shall be deemed to have come into force on the 17th day of June, 1995.

Amendment of article 16.

2. In the Constitution, in Part III, in article 16, for clause (4A), the following clause shall be substituted, namely:—

"(4A) Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and article 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or in article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotions, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the services of the State.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have been provided reservation in promotions since 1955. This was discontinued following the judgment in the case of Indra Sawhney *Vs.* Union of India, wherein it was held that it is beyond the mandate of Article 16(4) of the Constitution of India. Subsequently, the Constitution was amended by the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Act, 1995 and a new clause (4A) was inserted in article 16 to enable the Government to provide reservation in promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. Subsequently, clause (4A) of article 16 was modified by the Constitution (Eighty-fifth Amendment) Act, 2001 to provide consequential seniority to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates promoted by giving reservation.

The validity of the constitutional amendments was challenged before the Supreme Court. The Supreme Court while deliberating on the issue of validity of Constitutional amendments in the case of M. Nagaraj *Vs.* UOI & Ors., observed that the concerned State will have to show in each case the existence of the compelling reasons, namely, backwardness, inadequacy of representation and overall administrative efficiency before making provision for reservation in promotion.

Relying on the judgment of the Supreme Court in M. Nagaraj case, the High Court of Rajasthan and the High Court of Allahabad have struck down the provisions for reservation in promotion in the services of the State of Rajasthan and the State of Uttar Pradesh, respectively. Subsequently, the Supreme Court has upheld the decisions of these High Courts striking down provisions for reservation in respective States.

It has been observed that there is difficulty in collection of quantifiable data showing backwardness of the class and inadequacy of representation of that class in public employment. Moreover, there is uncertainty on the methodology of this exercise.

Thus, in the wake of the judgment of the Supreme Court in M. Nagaraj case, the prospects of promotion of the employees belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are being adversely affected.

Demands for carrying out further amendment in the Constitution were raised by various quarters. A discussion on the issue of reservation in promotion was held in Parliament on 3-5-2012. Demand for amendment of the Constitution in order to provide reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in promotion has been voiced by the Members of Parliament. An All-Party Meeting to discuss the issue was held on 21-08-2012. There was a general consensus to carry out amendment in the Constitution, so as to enable the State to continue the scheme of reservation in promotion for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as it existed since 1995.

In view of the above, the Government has reviewed the position and has decided to move the constitutional amendment to substitute clause (4A) of article 16, with a view to provide impediment-free reservation in promotion to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to bring certainty and clarity in the matter. It is also necessary to give retrospective effect to the proposed clause (4A) of article 16 with effect from the date of coming into force of that clause as originally introduced, that is, from the 17th day of June, 1995.

NEW DELHI;
The 4th September, 2012.

V. NARAYANASAMY

सं0 17020/18/2012-एस.सी.डी. (आर.एल.सैल)
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1
दिनांक: 18 /06/2013

सेवा में,

श्री पाराशर नारायण शर्मा,
68 भारतेन्दु नगर, खातीपुरा,
जयपुर, राजस्थान ।

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत श्री पाराशर नारायण शर्मा का आवेदन पत्र ।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने दिनांक 10/13.05.2013 के आवेदन पत्र का संदर्भ ग्रहण करें जो अधोहस्ताक्षरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा अन्तरित दिनांक 07.06.2013 को प्राप्त हुआ । आपके द्वारा चाही गई सूचना इस प्रकार है :-

1. किसी जाति आदि को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए अस्पृश्यता की पारंपरिक प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन को मानदण्ड माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 341(2) के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूचियों में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों की सूची में संशोधन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रक्रियाएं निर्धारित की गयी हैं जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों की सूचियों में संशोधन का कोई प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा आवश्यक नृजातीय सामाग्री सहित प्रस्तावित होना अपेक्षित होता है जिसे भारत के महारजिस्ट्रार एंव राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के परामर्श से प्रसंस्कृत किया जाता है।

2. वर्ष 1956 के बाद राजस्थान की अनुसूचित जातियों की सूची में किसी जाति का समावेश/अपवर्जन नही किया गया। वर्ष 1976 में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा कतिपय जातियों के संबन्ध में लगा क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाया गया था ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत श्री संजीव कुमार, संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है।

भवदीय,
(आर. पी. पुरी)
अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

संख्या: 17020/18/2012-एस.सी.डी. (आर.एल.सैल) दिनांक /06/2013

प्रतिलिपि: 1. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 5वी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली के पत्र संख्या पी-18//RTI/93/2013-एसएसडब्ल्यू -1 दिनांक 30.05.2013 के संदर्भ में ।

2. अनुभाग अधिकारी, जन सूचना केन्द्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके कार्यालय ज्ञापन सं.305/एफसी एंड आरटीआई/2013, दिनांक 05.06.2013 के संदर्भ में।

(आर. पी. पुरी)
अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

F. No. 16016/6/2011-C&LM-I (Rajasthan)
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
C&LM Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 13th June, 2013,

To,

Shri Parashar Narayan Sharma,
68, Bharatendu Nagar,
Khati Pura, Jaipur,
Rajasthan.

Subject: **Furnishing Information under the RTI Act, 2005.**

Sir,

Please refer your RTI application No. 19134 dated 10/13.5.2013 transferred by the National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi vide its letter No. PNS/RTI/22/Dev./Jaipur/2013/RU-I dated 21.5.2013 (received in this Ministry on 28.5.2013). The point-wise information is as under:-

(i) The Scheduled Tribes are specified under Article 342 of the Constitution, the criteria followed for specification of a community as a Scheduled Tribe are:-

- Indications of primitive traits,
- Distinctive culture,
- Geographical isolation,
- Shyness of contact with the community at large, and
- Backwardness.

(ii) The Copies of the Constitutional Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 in relation to the State of Rajasthan, are enclosed. The Ministry of Tribal Affairs was created in 1999 and the copies of the corresepondence and related reports/documents in connection with the notification of communities as STs in 1956/1976 are not available in this Ministry.

Hindi version follows.

Yours faithfully,

Purnima 13/6-13

(Purnima Tudu)
Under Secretary & CPIO
Tel. 23074408

[NB. In terms of Section 19 (1) of the Right of Information Act, 2005, Dr. Namita Priyadarshee, Director, in the Ministry of Tribal Affairs {Room No. 722 "A" Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001; Tel. No. 23073176 (Office) has been designated as Appellate Authority for the Ministry of Tribal Affairs for the purpose of the implementation of the Right to Information Act, 2005].

Copy to: (i) U.S. (PC&V) w.r.t. their Dy No. 102 dated 28.5.2013.

C:\Documents and Settings\admin\Desktop\MY Files\RTI\rti cor.doc

①

F.No. 11030/01/2013-C&LM-I
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
C&LM Division
******

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 26th August, 2013

To,
Shri Ratan Kumar,
Plot No. 21,Shubham Vihar,
(Kajod Colony), Mahesh Nagar,
Jaipur- 302015,
Rajasthan.

Subject: **Furnishing of Information under RTI Act, 2005.**

Sir,

Please refer to your application dated 15.3.2013 transferred by the Department of Social Justice & Empowerment vide its O.M. No. 17020/3/2013-SCD (RL Cell) dated 10.7.2013.

It is to inform you that the "Meena" मीणा community has not been included in the list of Scheduled Tribes in Rajasthan. However, a copy of relevant part of Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 (No. 108 of 1976) in relation to the State of Rajasthan, is enclosed.

Yours faithfully,

Purnima 26/8/13
(Purnima Tudu)
Under Secretary & CPIO
Tel. 23074408

[NB. In terms of Section 19 (1) of the Right of Information Act, 2005, Shri Rajeev Prakash, Director, in the Ministry of Tribal Affairs (Room No. 722 "A" Wing, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001; Tel. No. 23073178 (Office) has been designated as Appellate Authority for the Ministry of Tribal Affairs for the purpose of the implementation of the Right to Information Act, 2005].

Copy to: (i) Shri R.P. Puri, Under Secretary & CPIO, Ministry of Social Justice & Empowerment, Shastri Bhawan New Delhi w.r.t. their O.M. No. 17020/03/2013-SCD- (RL Cell) dated 10.7.2013.

(ii) U.S. (PC&V) w.r.t. their Dy No. 205 dated 12.7.2013.

Rajasthan

ED 09047801 2IN

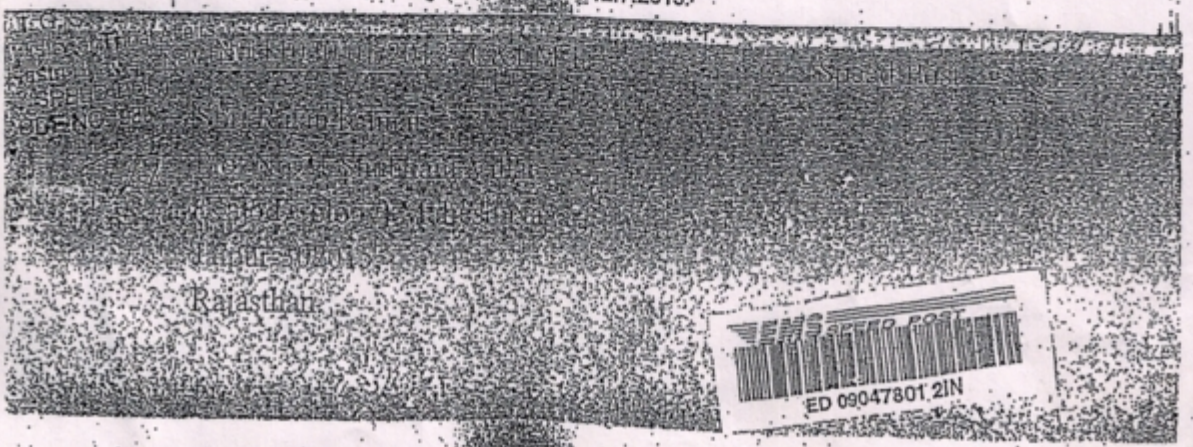

(89)

Anx c-11

Certified P.S. Copy of order dt. 18/2/14.

8 Anx-11

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT

JODHPUR

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 13978/2013

Sugan Lal Bhil S/o Shri Nand Lal Bhil, Age 35 years, R/o Mukam Post Raita, Panchayat Samiti Begu, District Chittorgarh.

...PETITIONER

VERSUS

1. State of Rajasthan through Additional Chief Secretary, Rural Development & Panchayati Raj Department, Government Secretariat, Jaipur.

2. Principal Secretary, Department of Personnel, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.

3. Director, Elementary Education, Bikaner.

4. Chief Executive Officer, Zila Parishad, Chittorgarh.

सही प्रतिलिपि
19 FEB 2014
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

5. Shri Ganpath Lal Meena S/o Shri Narayan Lal Meena, R/o Shri Narayan Lal Meena, R/o Gram Pachundal, Post Shadi, District Chittorgarh-3012022.

6. Shri Kunj Bihari Meena S/o Shri Hari Om Meena, R/o Dheebri Kali Sindh, Post Jaloda Khatiya, Tehsil Peepalda, District Kota-325214.

OATH COMMISSIONER
REVENUE, CRIMINAL, CIVIL
RAJ. HIGH COURT, JODHPUR

(95)

Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 (No.108 of 1976) in relation to the State of Rajasthan is enclosed.
Yours faithfully,
Sd/-
Under Secretary & CPIO"

In view of the above, apparently it appears that certificate of ST can be issued to caste of "mina" (मीना) but, for the said purpose, the clarification is to be made by the State Government.

Therefore, copy of this order may be sent to the Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur with direction to examine the matter and issue necessary directions within a period of one month from the date of receiving certified copy of this order. Copy of this order may be supplied along with photo-stat copy of communication dated 26.08.2013 (Annex.-12) to the Addl. Advocate General to communicate the same to the Chief Secretary of the Government of Rajasthan. The Deputy Registrar (Judl.) of this Court is directed to send copy of this order along with copy of letter dated 26.08.2013 (Annex.-12) directly to the Chief Secretary, Government of Rajasthan, Jaipur for compliance.

List this matter for compliance and report to this Court on 05.04.2014.

(Gopal Krishan Vyas) J.

Ojha, a.

सही प्रतिलिपि
28 FEB 2014
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक
राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

P.T.O.